

उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने किया दो दिवसीय समावेशी मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन

जन सरोकारों का दर्पण बने मीडिया

- पत्रकारों से खबरों के जरिए लोकतांत्रिक चेतना के प्रसार की ओरी

भास्कर न्यूज | छत्ती

लोकतंत्र की मजबूती के लिए मीडिया के एजेंडे का जनपक्षधर होना आवश्यक है। जनसरोकारों का दर्पण बने बिना मीडिया लोकतांत्रिक चेतना का बाहक नहीं बन सकती है। आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि गांवों की आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था में बदलाव किए जाएं। ये बातें उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहीं। वे सोमवार को होटल बीएनआर चाणक्य में दो दिवसीय समावेशी मीडिया कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे।

विकेन्द्रित योजना के निर्माण में क्षेत्र विशेष की स्थिति व उसकी प्राथमिकताएं तय करने की ज़रूरत बताते हुए उन्होंने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मीडिया की भूमिका पर बल दिया। योजना एवं विकास सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना आज बेहद चुनौती भरा काम है। उन्होंने लोकतंत्र के विकंट्रीकरण को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी बताया। कार्यशाला में राज्य के विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों के अलावा पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यशाला का आयोजन यूएनडीपी एवं इंक्लूसिव मीडिया फॉर चैज द्वारा किया गया।



होटल बीएनआर चाणक्या में मीडिया कैपिसिटी पर यूएनडीपी के सेमिनार में बोलते उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो।

मीडिया निभाए सकारात्मक भूमिका

यूएनडीपी के गवर्नेंस सलाहकार टीआर रघुनंदन ने कहा कि योजनाओं की सही जानकारी आम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मीडिया की ही है। उन्होंने योजना के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिंधु घाटी और रोमन सभ्यता के समय से ही योजनाओं की शुरुआत हुई। लेकिन आज के दौर में योजनाओं की रूपरेखा पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने योजना बनाने और उसे लागू कराने में आवे वाली कठिनाइयों के व्यावहारिक पक्षों पर जर डालते हुए कहा कि आज मीडिया को सामने आकर इस विषय पर पहल करनी चाहिए। योजना आयोग के प्रोग्राम थ्रॉनिट से जुड़े विशेषज्ञ सुंदर एन मिश्रा ने प्रश्नाशन के विकेंट्रीकरण के नाम पर जिटल केंट्रीकरण की प्रक्रिया अपनाएं जाने की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही संवैधानिक अधिकार दिए जाने के बाबजूद स्थानीय स्तर के विरोधाभासी अधिनियमों की बाधाओं को दूर करने पर बल दिया।

गांवों को विशेष अधिकार मिले

कार्यशाला के दो सत्रों में एसएन बिश्वा और प्रो प्रेमेश शरण ने भी अपने विचार रखे। रमेश शरण ने पेसा कानून के विभिन्न पहलुओं से लोगों को अवगत कराया। सुधीर पाल ने गांवों को विशेष अधिकार दिए जाने की बात कही। प्रश्नोत्तर सेशन में प्रतिभागियों की चिंताओं का समाधान भी दिशेषज्ञों द्वारा किया गया। सचालन इंक्लूसिव मीडिया फॉर चैज के विपुल मुद्घल ने किया।

जन-संवेदना का साक्षात्कार करें पत्रकार

दिल्ली के थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी से जुड़े मीडिया एक्सपर्ट विपुल मुद्घल ने कहा कि जन-संवेदना का साक्षात्कार कर ही पत्रकार अपने समाचारों के दायरे का विस्तार कर सकते हैं। सामाजिक पूँजी का संग्रह ही किसी पत्रकार के लिए नए विचारों का स्रोत होता है। जो उनके पेशेवर जीवन में भी सफलता देता है।